Governments in not providing the necessary funds for having common effluent treatment plants.

I am afraid that in future there may be a shortfall in export of leather and that there may be production of substandard leather because quality leather processing units have been closed down.

So, who is responsible for not providing funds for constructing effluent treatment plants in those places? Is there any possibility of reduction in the export of leather products in future? Is there any possibility of exporting substandard leather to Russia and other foreign countries?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, although this supplementary does not directly arise from this question, I would be happy to answer this. If anyone is responsible for the situation in which the leather-goods manufacturers in Tamil Nadu find themselves today, it is the Council which is unwilling to take action against a handful of people who have frustrated the will of the Council.

Sir, we used to levy a cess on leather exports. It was coming to the Consolidated Fund. It was transferred to the Council for Leather Exports. The Council represented that this was an inefficient system and that they should allowed to levy the cess themselves, to collect it and to spend it on common effluent-treatment facilities as well as other common facilities. The Finance Minister kindly agreed to my recommendation. So, in the last Budget in 1995, we withdrew this tax. We gave the Council the power to levy the cess. The Council solemnly resolved to levy the cess. Two or three persons went to the Court and challenged it. The Court struck it down. Now there is an appeal with the Supreme Court.

All that I can do is to request the Finance Minster to re-impose the tax, but that can take place only in June. The point is that if a handful of people, just three or four, could frustrate the collective will and wisdom of a thousand members of the Council for Leather Exports, they have to blame themselves. Despite that, we are willing to support them for setting up common effluent-treatment facilities. But, I think, they must have the will either to manage their affairs themselves or to ask the Government to levy the tax, to collect it and to give it to them. it is entirely their choice. But, I am now recommending to the Finance Minister that as they cannot solve this matter, we should re-impose the tax.

Problem of Child Labour and Assistance from Foreign Countries

*143. SHRIMATI KAMLA SINHA:
DR. BAPU KALDATE:†

Will the Minister of LABOUR be please to state:

(a) whether it is a fact that Government have rejected the help offered by certain countries to check the problem of child labour,

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) what strategy has been adopted by Government so fare to tackle the problem and what are the results achieved?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

The Government is concerned about the widespread prevalence of child labour in India and is also very serious about its elimination. Government has also taken several steps to tackle the problem of child labour through legislation, general development programmes for the benefit of children and poor and implementation of National Child Labour Projects. A major programme was announced in August, 1994 for elimination of child labour in hazardous employments. Under this scheme an estimated two million

† The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Bapu Kaldate.

children engaged in hazardous employments in India are sought to be taken out of the world of work by the year 2000 A.D. It is estimated that about Rs. 850 crores would be required to implement the programme to eliminate child labour in hazardous employments by 2000 A.D. Substantial and adequate funds have been committed by the Government to implement this programme. India has, therefore, preferred to depend on its own resources to curb this social evil.

For the year 1995-96, the Planning Commission has alloted Rs. 34.4 crores to implement child labour elimination programmes. During the current year 63 national child labour projects have been approved. This is in addition to 12 on-going national child labour projects. In all, more than 2200 special schools have been sanctioned to cover around 1.36 lakh children in the child labour endemic States of Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat, Orissa, West Bengal, Bihar, Rajasthan, Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu. Child labour endemic districts numbering 123 have been sanctioned funds to carry out surveys to identify child labour engaged in hazardous occupations. The survey will be preceded by an exercise to categrorise occupational hazards-intensity wise-to cover children engaged in most hazardous occupations on priority.

डा० बापू कालदातेः सभापति जी, बाल मजदूरों की समस्या सही मायने में दरिद्रता की ही समस्या है। खुशी से कोई बच्चा, जिसको आपने हैज़र्डस कहा है, ऐसे उद्योगों में नहीं जाएगा अगर उसकी आर्थिक अवस्था ठीक हो तो। लेकिन जिस ढंग से आपने उत्तर दिया है उससे मुझे दो बातें लगती हैं—एक तो आपका उत्तर अस्पष्ट है और मुझे इसमें सरकार की गंभीरता नज़र नहीं आ रही है। मैं आपके जवाब से ही दो-तीन बातें पूछना चाहूंगा कि एक तो कितने मजदूर हैं, इसके बारे में कोई गिनती या सेंसस् जिसको कहते हैं, ऐसा हुआ है क्या? जहां तक हमारी जानकारी है, यह कहा जाता है कि 25 मिलियन चाइल्ड लेबर हैं और उसमें हर साल चार प्रतिशत बढ़ोत्तरी हो रही है। तो क्या सरकार ने कभी इन लोगों की गिनती की है? यह तो हैज़र्डस वाले छोड़िए लेकिन जो साइकिल की दुकान पर काम करते हैं, होटल में मजदूरी का काम करते हैं, ऐसे कई हैं। तो मैं पहला सवाल तो यही पूछूंगा कि क्या सरकार ने गिनती की है या गिनती के बारे में कुछ सोच रही है? अगर की है तो कितनी है और अगर नहीं की है तो कब करने वाले हैं?

श्री जी० वेंकटस्वामीः सभापति महोदय, आनरेबल मेंबर ने जो सवाल पूछा है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि 1981 के सेंसस के लिहाज से 13.6 मिलियन बच्चे हैजर्डुअस उद्योगों में काम कर रहे हैं। अभी 1991 का सेंसस डाटा पूरी तरह से नहीं आया है। जब वह हमारे सामने आ जाएगा, तभी मैं आनरेबल मेंबर को बता पाऊंगा। महोदय, आनरेबल मेंबर ने कहा कि इनकी गिनती बढ़ती जा रही है। यह बात सही है कि पापुलेशन बढ़ती जा रही है और बालकों की गिनती भी बढ़ती जा रही है तो इस लिहाज़ से इन हैजर्डुअस उद्योगों में भी इनकी गिनती बढ़ रही होगी। इसकी फिगर मैं आनरेबल मेंबर को 1991 की सेंसस रिपोर्ट आने के बाद ही बता सकूंगा।

डा० बापू कालदातेः महोदय, आपने खुद कहा है कि जो कुछ भी आपने सोचा है, उसके मुताबिक 850 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, अगर आपको सन् 2000 तक इसको पूरा करना है और आपके जवाब में नीचे आपने लिखा है कि 1995-96 में प्लानिंग कमीशन ने आपको सिर्फ 34 करोड़ रुपए दिए हैं तो कैसे आप सन् 2000 तक इसको पूरा करेंगे? अब तो 1996 में हम लोग आ पहुंचे हैं। केवल 4 साल बचे हैं। आपको 850 करोड़ रुपए की जरूरत है और 34 करोड़ रुपए आपके हाथ में हैं। तो हमारी समझ में नहीं आता कि आप इसको कैसे करेंगे?

मेरी जानकारी के अनुसार यूरोपियन कम्युनिटी के लोग चाहते थे कि आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दें लेकिन आपने नकार दिया है कि हमको नहीं चाहिए क्योंकि हम हमारे बलबूते पर करना चाहते हैं। तो क्या आपकी सरकार हर साल 34 करोड़ देकर सन् 2000 तक 850 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर सकेगी? अगर नहीं कर सकेगी तो इसके बारे में आप क्या करना चाहते हैं?

महोदय, इसी से जुड़ा दूसरा सवाल यह है कि आपने 2200 स्पैशल सेंटर्स खोले हैं It covers only 1.36 lakh children. आप ही खुद कह रहे हैं कि ऐसे बच्चों की संख्या 25 मिलियन तक हो सकती है। इसमें से 1,36,000 बच्चों के लिए व्यवस्था आपने की है। तो 25 मिलियन बच्चों की व्यवस्था करने के लिए आप

850 करोड़ रुपए की धनराशि कैसे इकट्ठा करेंगे? एक तरफ है 34 करोड़ और 1,36,000 बच्चों की व्यवस्था और दूसरी तरफ है 850 करोड़ और 25 मिलियन बच्चों की व्यवस्था, इसमें कोई तालमेल नहीं है। Is the Government really serious? Has the Government taken it like a crash programme?

ऐसा कोई एक प्रोग्राम आप बनाना चाहते हैं? अगर इसी ढंग से चलाते रहेंगे तो सिर्फ तादाद बढ़ती रहेगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो क्या सरकार सही मायने में सन् 2000 तक 850 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर सकेगी हैजर्डुअस उद्योगों में काम कर रहे बच्चों के लिए बाकी उद्योग तो अलग हैं। इसके लिए सरकार कौन से ठोस कदम उठाना चाहती है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

श्री जी० वेंकटस्वामी: सभापति महोदय, आनरेबल मेंबर का सवाल एक हद तक सही है कि प्राईम-मिनिस्टर ने चाईल्ड लेबर के ऐबोलिशन के लिए 850 करोड़ रुपए दिए जाने का एनाऊंसमेंट किया है। इसके बाद ही गवर्नमेंट आफ इंडिया, मिनिस्ट्री आफ लेबर ने सारे हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट कलक्टर्स की कान्फ्रेंस करके जोर-शोर के साथ यह काम शुरू करवाया है। महोदय, 70 डिस्ट्रिक्ट्स में यह काम शुरू हो चुका है।

डा० बापू कालदाते: 123 डिस्ट्रिक्ट्स में आपने सर्वे के लिए कहा है।

श्री जी० वेंकटस्वामी: मैंने काम शुरू कर दिया है। सर्वे भी इसलिए किया जा रहा है ताकि मालूम हो सके कि कहां चाईल्ड लेबरर्स काम कर रहे हैं, किसको निकालना है उस उद्योग से, किसको स्कूल में रखना है, किसको स्टाइपेंड का ऐश्योरेंस देना है, किसको मिड-डे मील का इंश्योरेंस देना है... **(व्यवधान)**

डा० बापू कालदाते: सन् 2000 तक तो हम सर्वे ही कर पाएंगे।

श्री जी० वेंकटस्वामी: सभापति महोदय, काम शुरू हो चुका है और मैं समझता हूं कि सन् 2000 तक हम यह कर पाएं तो गनीमत है। इसे हमारी खुश किस्मती कहिए या बदकिस्मती कहिए कि जब से मैं टैक्सटाईल, मिनिस्टर बना हूं।

अध्यक्ष जी, उसमें असल झगड़ा वहां से शुरू हुआ है यह जो फारेन ऐड के लिए क्वेश्चन में बात आई है, वह यह कि जर्मन लेबर मिनिस्टर यहां आए थे। मुझसे मिले, उसके बाद श्री माधवराव सिंधिया से मिले, उसके बाद श्री संगमा, लेबर मिनिस्टर से मिले। बड़े खुशहाल यहां से गए थे। यहां से जाने के बाद उनकी डायरी में निकला हुआ पहली बार सारे न्यूजपेपर्स में और टी०वी० में छपा।... **(व्यवधान)**

डा० बापू कालदाते: बहुत लोगों के पास डायरियां हैं....**(व्यवधान)**

श्री जी० वेंकटस्वामी: जरा सुनिए आप। आई० एल० ओ० हमारे यहां चाईल्ड इरेडिक्शन और अबोल्यूशन के लिए देते है। तो वह कितना देते है— 14 करोड़ के करीब वह लोग देते हैं। अध्यक्ष जी, हमेशा यह कहना कि हिन्दुस्तान में चाइल्ड लेबर से ही काम लिया जाता है, सही नहीं है, बल्कि वर्ल्ड में हमारा सबसे बिगेस्ट मार्केट है इन जर्मनी और वहां के मिनिस्टर साहब टी०वी० से एनाउंस करते हैं और कारपेट पर रंग डालते हैं तथा बतलाते हैं कि इस पर चाइल्ड लेबर का ब्लड है इसको मत खरीदो। वह थोड़ा सा पैसा देते हैं और हिन्दुस्तान के हमारे बच्चों को क्वेश्चन मार्क करके हमारे ट्रेड को और हमारी चाइल्ड लेबर को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हमारी चाइल्ड लेबर कारपेट इण्डस्ट्री के अंदर है उसको दो साल के अंदर हमने एक परसेंट कम किया है और इसको करने के बाद हमने लेबर मिनिस्टर को एश्योरेंस दिया कि—हम नहीं बोलते कि हमारे पास नहीं है, जैसा तुम छिपाते हो अपनी खामियों को। मैंने वर्ल्ड के पार्लियामेंटेरियन से अपील की कि जो चाइल्ड लेबर हमारे पास हैं उसके बारे में हमने प्लान बनाया तथा इसको दो हजार तक कम करने की कोशिश करेंगे। मगर बड़ी बुरी तरह से सिर झुकाना पड़ता है वर्ल्ड के पार्लियामेंटेरियन को। डवलपिंग व अंडर डवलपिंग कंट्रीज के चाइल्ड प्रोस्टीट्यूशन को पहले रोकना है। मैंने जर्मनी के अंदर जाकर सवाल किया—तुम हमको क्या सवाल करते हो, पहले अपने दामन को देखो कि तुम्हारे जर्मनी में तीन लाख बच्चियां प्रोस्टीट्यूशन में इंवोल्वड है, पहले उस तरफ देखा जाना चाहिए।...**(व्यवधान)**

डा० बापू कालदाते: यह तो मैं समझ गया। लेकिन यह बताइए कि आपने जो धनराशि दी है और आपको जो प्रत्यक्ष आवश्यकता है उसमें जो गैप है वह आप दो हजार तक कैसे पूरा करेंगे?

श्री जी० वेंकटस्वामी: मैं आता हूं। मैं पहले क्वेश्चन का जवाब दे दूं। हमने क्यों रोका। अध्यक्ष जी, जर्मनी में ही नहीं बल्कि अमेरिका में हरकिन बिल लाया गया है। हिन्दुस्तान के बच्चों से हम काम ले रहे हैं, इसके लिए वहां पर बुलाया। एक मर्तबा बुलाया तो गया। फिर कोशिश कर रहे हैं। इसमें बिजनेस इंटरेस्टेड पीपुल, वोल्यूंटरी आर्गनाइजेशन को लेकर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो हैं एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की तरफ जा रहे थे।

हमने समझा कि अपने बच्चों को हम देखेंगे और इसलिए प्राईम मिनस्टर ने एकदम एनाउंस किया कि 850 करोड़ से स्टार्ट करो दो हजार तक और जरूरत पड़ी तो हम देंगे। अबोल्यूशन आफ चाइल्ड लेबर, इरेडिक्शन आफ चाइल्ड लेबर के लिए पूरी तरह उसमें कम करेंगे।

आनोरेबिल मेंबर का सवाल यह था कि आप 850 करोड़ में किस तरह काम करें। इब्तदाए इश्क है, देखो होता है क्या।

DR. BAPU KALDATE: There is no answer to my question. How are they going to fill the gap? That is the point. You are only spending Rs. 34 crores. The requirement is Rs. 850 crores. Sir, he has said nothing about it. It is no use just assuring...*(Interruptions)*.

श्री जी० वेंकटस्वामी: अध्यक्ष जी, अभी काम शुरु हुआ है। मैं पूरी तरह से इस काम में लगा हुआ हूं। एक तरफ टैक्सटाइल्स में जिसके बारे में यह क्वेश्चन था, वहां पर कारपेट में कालीन लेविल लगाकर उनके मुंह के ऊपर वह बता रहे है कि देखो। हम अपने चाइल्ड लेबर फ्री कारपेट बेच रहे हैं। इस तरह से एक-एक काम शुरू करके इधर ट्रेड को भी बचाना है, हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनियां में अपने कारपेट ट्रेड को आगे बढ़ाना है। उसका भी काम शुरू हुआ है। खास तौर से हर डिस्ट्रिक्ट में जहां कहीं मैं जाता हूं वहां मैं पहले देखता हूं कि कितने स्कूल खुले हैं। कितने चाइल्ड लेबर को लाकर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको स्कूल में सिखला रहे हैं। यह सारी चीजें मैं देख रहा हूं। आनोरेबिल मेंबर को मैं विश्वास दिलाता हूं कि कि आयन्दा दो हजार तक का जो है उस तक हम अपनी चाइल्ड लेबर को बचाने की कोशिश करेंगे।

श्री चतुरानन मिश्र: सभापति महोदय, बच्चों की, चाइल्ड लेबर की समस्या बहुत जटिल है और यह शर्मनाक भी है लेकिन यह गरीबों से सीधे जुड़ी हुई है। कोई मां-बाप नहीं चाहता कि वह अपने बच्चों को निरक्षर रखे। हकीकत यह है कि हर एक बच्चा जो गरीब का है, गांव में लोग बकरी चराने के लिए, भैंस चराने के लिए, गाय चराने के लिए अपने बच्चों को भेज देते है और उस से उनकी इन्कम होती है। मैं ऐसे उद्योगों को जानता हूं जहां एक्सपोर्ट भी होता है। जैसे माइका है, इससे सिलीकोसिस हो जाता है बच्चों को। कई बार मैंने इस संबंध में सवाल भी उठाया लेकिन श्रम मंत्रालय ने कुछ नहीं किया है। मैं समझता हूं कि सरकार से यह गलती हो रही है, ये काम सिर्फ श्रम मंत्रालय का नहीं है यह काम होल गवर्नमेंट का है। अगर यह 850 करोड़ रुपये में होता है तब तो हम आपको बधाई देते हैं, परन्तु यह आठ हजार करोड़ रुपये में भी नहीं हो सकता है। यदि प्रधान मंत्री सीरियस हैं, मुझे शक है कि सीरियस हैं, 850 करोड़ रुपये में कुछ नहीं होगा। मंत्री महोदय, आगे क्या-क्या होता है, हम आपको बताना चाहते हैं कि आठ हजार करोड़ रुपये से भी हो जाये तो हम खुश होंगे। इसीलिए प्रधान मंत्री को कहिए कि एक जनरल सैस हरेक इण्डस्ट्री पर, फूड कारपोरेशन पर अगर आप दो पैसे पर-किलो जनरल से मिलगा; तो उससे हम लोग मर नहीं जायेंगे।

अगर आप दो पैसा उन पर एनुअली सैस लगा दें तो दो हजार करोड़ रुपया मिलेगा।

इसीलिए मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इसके सर्वांगीण रूप में सिर्फ श्रम विभाग ही नहीं, बल्कि सरकार पूरे तौर पर विचार कर के इसके लिए कोई ऐसा, सैस कन्ट्री भर में लगाएगी जिससे उनको दिया जा सके, ताकि वे पढ़-लिख सके और कुछ काम सीख सके और कर सके? यह काम भी क्या यह सरकार करेगी या यह सिर्फ श्रम मंत्रालय का बच्चा समझा जाएगा? चाइल्ड लेबर अगर पूरे राष्ट्र में है तो पूरे राष्ट्र को डिवोट करना है इसके बारे में आप क्या कदम उठा रहे हैं?

श्री जी० वेंकटस्वामी: मैं आनरेबल मेम्बर के सजेशन को बहुत एप्रिसिएट करता हूं। ये आठ सौ करोड़ रुपये में क्या दो हजार साल तक हो सकता है, क्वेश्चन यह है। सभापति जी, मैंने उसका भी हिसाब निकाला है और कम से कम दो हजार करोड़ रुपये की जरूरत है। जैसा आपने सुझाव दिया कि हर एक मिनिस्ट्री के अन्दर हमारी चाइल्ड लेबर का इन्वाल्वमेंट है इसलिए सारी मिनिस्ट्री इसके बारे में मीटिंग वगैरह करके और स्टेटिस्टिक्स लेकर इसका उपयोग करें तथा उनसे कहा जाये कि आप अपनी-अपनी मिनिस्ट्री में चाइल्ड लेबर के एबोलिशन के लिए काम करें, इसलिए मैं आनरेबल मेम्बर के सजेशन को कबूल करता हूं। प्रधान मंत्री जी ने सारी मिनिस्ट्रीज की मीटिंग में इस बात को फस्ट टाइम लिया है कि हमारे यहां जो पैसा बाहर से आता है, वह पैसा कम है और बदनामी ज्यादा है, इसलिए उसको बन्द किया जाय और अपने कदमों पर खड़े रहने के लिए जो सुझाव दिया है, मैं प्रधान मंत्री जी को बताकर सारी मिनिस्ट्रीज को इसमें इन्वाल्व कर के, यह जो धब्बा है इसको जल्दी से जल्दी मिटाने की कोशिश करूंगा।

ABHINANDAN JAIN: Thank you very much, Sir. The hon. Minister has stated that the Government has taken several steps to tackle the problem of child

labour through legislation-general development programmes. There is no doubt that *bona fide* efforts have been made, to tackle the problem of child labour. But I must point out to the hon. Minister that sufficient steps have not been taken. In Parliament and outside Parliament, we have been demanding that the Government should come up with a legislation to put a ban on child labour. I am asking a very specific question. Will the Government show the political will to come up with a legislation to put a ban on child labour? Secondly, in our Directive Principles of State Policy, we have declared that free and compulsory education will be provided to children. Will that be made really compulsory *in order to take these children* out of child labour and send them to schools?

श्री जी० वेंकटस्वामी: सभापति जी, लेजिस्लेशन के लिए, गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इससे पहले भी बहुत सारे ऐक्शन लिए हैं और ऐक्ट के लिए भी लिए हैं। आनरेबल मेंबर को जानना चाहिए कि चाइल्ड लेबर ऐक्ट की शुरुआत हुई है। काम भी उसमें शुरू किया जा रहा है। आनरेबल मेंबर ने यह भी पूछा है कि इसमें किस तरह से काम किया है, कहां तक किया है, ये सारी बातें पूरे स्टेटिस्टिक्स के साथ मैं उनको भिजवा दूंगा।

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति जी, मैं बाल श्रमिक और विशेषकर इस देश के बच्चों के प्रति जो क्रूरता बरती जा रही है, मंत्री जी से इसके बारे में साफ जवाब चाहूंगा। दुनिया में शायद हिन्दुस्तान के बच्चे सबसे ज्यादा मार खाते हैं। मां-बाप से लेकर स्कूल मास्टर तक। अगर वे किसी उद्योग में काम करते हैं तो वहां भी मार खाते हैं। उद्योगपतियों को यह सहूलियत होती है कि ज्यादा उम्र के होने के बाद वे अधिकार चेता हो जाते हैं और मारकर उनसे काम नहीं लिया जा सकता है। लेकिन हिन्दुस्तान के उद्योगपति कहीं कहीं क्रूरता का परिचय देकर, मारकर इन बच्चों से काम लेते हैं। क्या सरकार के पास कोई विशेष कानून सख्त सजा देने वाला कानून है जिससे हिन्दुस्तान में बच्चों को पीटा न जाए, चाहे स्कूल में हो या अपने मां-बाप द्वारा या किसी किसी उद्योग में, क्या कोई ऐसा सख्त कानून सरकार के पास है जिससे खासतौर से उद्योगों में जो बच्चे काम कर रहे हैं उनकी रक्षा की जाए?

श्री जी० वेंकटस्वामी: सभापति जी, हां है और स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से हजारों केसेज में प्रासीक्यूट किया है और ऐक्शन लिया है। मैं आनरेबल मेंबर को विश्वास दिलाता हूं कि आइंदा ऐसा कोई कानून बना सकते हैं, ऐसा कोई ला सकते हैं। जो आपने सजेस्ट किया है उसके बारे में भी हम गौर करेंगे।

SHRI V.P. DURAISAMY: Sir, the Tamil Nadu Government is supposed to be the best Government in providing necessary assistance to children. All the school going Scheduled Caste and Scheduled Tribe children are being paid monthly Rs. 50/-, Rs. 100/- and Rs. 200/- as incentive money other than the scholarships in order to eradicate child labour. Now I want to know from the Labour Minister whether the Government has got any idea to give any incentive money to the Scheduled Caste children, and also whether the Government will come forward to provide rehabilitation centres for the deprived children and the victims of child labour. And thirdly as the foreign aid is accepted by the Government of India, I want to know whether the same facilities can be extended to the State Governments to eradicate child labour.

श्री जी० वेंकटस्वामी: सभापति जी, चाइल्ड लेबर के बारे में रिजर्वेशन की जो बात है, हिन्दुस्तान में चाइल्ड लेबर के लिए जो बात हो रही है, उनके लिए एक ही तरह की देखभाल करना गवर्नमेंट और हम सब का फर्ज हो जाता है। उनमें अंतर करना, बचपन से ही, यह बात ठीक नहीं है। सब को साथ लेकर चलना होगा और उन सारे बच्चों को एक साथ ट्रेनिंग देंगे और एक साथ बिठाकर देंगे। इससे ज्यादा फायदा होगा। सभापति जी, दूसरा जो एड के बारे में बात कही है, उसके बारे में मैं जवाब दे चुका हूं।

SHRI PARAG CHALIHA: Sir, my supplementary does not specifically relate to the main question but it is a general implication. Will the Minister be pleased to state whether the Government is satisfied with the implementation of the Child Labour (Abolition) Act? We have seen that in the tea gardens of Assam hundreds and thousands of child labourers are being absorbed.

SHRI G. VENKAT SWAMY: Sir, the law is applicable everywhere and these Assam tea gardens are not exempted. They also have this law..... *(Interruptions)*.....

SHRI AJIT P.K. JOGI: No one is avove law.

श्रीमती मालती शर्मा: महोदय, मैं यह पूछना चाहती हूं कि वैसे तो कानून बने हुए हैं, लेकिन हमारी आंखों के सामने, सड़क के ऊपर नाबालिक बच्चे रिक्शा चलाते हैं, फैक्ट्रीज में भी जाकर छोटे-छोटे नाबालिक बच्चे काम करते हैं। आप उनके लिए कानून बना देंगे कि वे बच्चे काम नहीं करेंगे, लेकिन वे किसी मजबूरी में काम करते हैं। क्या माननीय मंत्री जी उनके घर वालों को कोई आर्थिक मदद देने का काम करेंगे?

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कोयले का अवैज्ञानिक रूप से खनन

*144. **श्री अजीत जोगी:**
श्री एस०एस० सुरजेवाला:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में कतिपय कोयला खानों में कोयले के अवैज्ञानिक रूप से किए जा रहे खनन कार्यों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी किन-किन खानों की पहचान की गई है;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन कोयला क्षेत्रों में कोयला खनन कार्य वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित तरीके से किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा, कोयला खान क्रियाकलापों को, विस्तृत अन्वेषण तथा खान आयोजन के आधार पर किया जाता है। इस संबंध में उपलब्ध सूचना के अनुसार ये कंपनियां कोयला खनन संबंधी क्रियाकलापों को वैज्ञानिक तरीके से कर रही है।

Production of Foodgrains

*145. SHRI RAMACHANDRAN PILLAI:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) the production of foodgrains during the last three years, item-wise; and

(b) the requirement of foodgrains in the country at the end of the Eighth Five Year plan and by the end of the century?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) A statement showing the production of foodgrains during the last three years, item-wise is enclosed (*see* below)

(b) Taking into consideration the present level of consumption/demand, the requirements of foodgrains (including pulses) in the country at the end of the 8th Five Year Plan i.e. 1996-97 is estimated to be around 193 to 195 million tonnes. The demand for foodgrains is likely to increase @ 2.5 % to 2.75% per annum, upto the end of the century depending upon the rate of increase in population and per capita income.

Statement

Item-wise production of foodgrains during the last three years

(Million Tonnes)

CROP		1992-93	1993-94	1994-95
Rice	Kharif	65.24	70.72	71.40
	Rabi/Summer/	7.62	9.58	9.76
	Total	72.86	80.30	81.16
Wheat		57.21	59.84	65.47
Jowar	Kharif	9.38	7.28	6.06
	Rabi	3.43	4.13	3.14
	Total	12.81	11.41	9.20